प्रधानमंत्री द्वारा आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन
6 जनवरी 2009

हम आंतरिक सुरक्षा पर विचार-विमर्श करने के लिए एक वर्ष से कुछ अधिक पहले दिसम्बर, 2007 में मिले थे। तब से जो बारह महीने गुजरे हैं वो हमारे लिए बहुत कठिन रहे हैं। सुरक्षा स्थिति और भी जटिल हो चुकी है। पिछले साल की गई अनेक भविष्यवाणियां दुर्भाग्य से सच साबित हुई हैं। कुछ मामलों में आतंकवादी हमलों की संख्या और विस्तार कई गुणा हो गया है। मौजूदा परिस्थितियों में हम आंशिक या खंडित दृष्टिकोण सहन नहीं कर सकते। निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा के लिए हमें समन्वित सोच अपनाने की ज़रूरत है।

पिछले वर्ष के दौरान, हमें अपने देश के बाहर से संचालित आतंकी समूहों से गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। उनमें से कई इन देशों की शत्रु गुप्तचर एजेंसियों के सहयोग से काम करते हैं। हमारी संवेदनशीलताओं का शोषण करने का प्रयास किया जाता है और इस बार जैसा कि मुम्बई में आतंकी हमले में हुआ, वे सफल रहे हैं।हमारी समस्याएं इस तथ्य से कई गुणा बढ़ जाती हैं कि हमारे करीबी पड़ोस में सुरक्षा माहौल बेहद अप्रत्याशित और अनिश्चित है। हमारे कुछ पड़ौसी देशों की सरकारें बेहद कमजोर प्रकृति की हैं। सरकार जितनी कमजोर होती है वह उतने ही गैरजिम्मेदाराना ढंग से काम करने की तरफ प्रवृत्त रहती है। हमारे ऊपर हुए विभिन्न आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान का जिम्मेदार होना इसका स्पष्ट उदाहरण है।

हम विभिन्न प्रकार की बहु आयामी चुनौतियों का सामना करते हैं, परंतु सबसे अधिक गंभीर चुनौतियां वे हैं जो आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में विद्रोह के रूप में हमें दी जाती हैं। वामपंथी उग्रवाद प्राथमिक रूप से स्वदेशी है और हमारे घर से उपजा है। दूसरी तरफ, आतंकवाद ज्यादातर हमारे देश के बाहर, मुख्य रूप से पाकिस्तान प्रायोजित है जिसने आतंकवाद को सरकारी नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल किया है। पूर्वोत्तर में विद्रोह आय और संपत्ति में असमानता से उपजा है लेकिन यह भी पड़ोसी देशों के विद्रोही आंदोलनों के नेताओं को उपलब्ध कराए गए ठिकानों के कारण कायम है। इसलिए ये बुनियादी अंतर है, जिन पर हमें आंतरिक सुरक्षा चुनौती और उपर्युक्त तीनों खतरों से निपटने के तरीकों पर विचार करना है।

पिछले सम्मेलन में यह उल्लेख किया गया था कि आतंकवादी इस खतरे का दायरा बढ़ा रहे हैं। अब राजनीतिक, सैनिक और सुरक्षा के परे वे आर्थिक, बुनियादी ढांचे और प्रतीकों पर हमले करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस तथ्य का भी उललेख किया गया था कि अब ज़मीनी मार्ग के विकल्प के रूप में समुद्री मार्ग की तलाश की जा रही है और इसका इस्तेमाल करने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इसलिए, यह सुझाव दिया गया था कि हमारे समुद्र तटों की अधिक चौकसी और अपनी जल सीमा में समुद्री गतिविधि की बेहतर निगरानी की जानी चाहिए। जिन आतंकवादियों ने 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर हमला किया, उन्होंने समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया और वे हमारी तटीय प्रहरियों से बचने में सफल रहे।

इस प्रकृति की सुरक्षा चुनौतियों की गणना करना और उससे निपटना अपने आप में इस दौर की जटिल चुनौती है। जिन परिस्थितियों का मैंने अभी अभी उल्लेख किया है उनमें तो यह और भी चुनौतीपूर्ण

बन गया है। हमारा सुरक्षा आकलन अनेक सूक्ष्म कारकों का मेट्रिक्स है, मगर दो बुनियादी और महत्वपूर्ण पहलू हैं अर्थात देश की क्षेत्रीय एकता की सुरक्षा और अपनी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

इस प्रकार के खतरों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीयता की मजबूत भावना महत्वपूर्ण है। हमारा राष्ट्र बाहरी चुनौतियों के साथ साथ आंतरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे निश्चय के साथ स्पष्ट रूप से एक है। राष्ट्रीयता की हमारी भावना बहु-नृजातिविषयक, बहुधर्मी, बहु-जातीय और बहु-भाषी समाज के हमारे महान ऐतिहासिक अनुभव से उपजी है। आज, जब पाकिस्तान युद्धोन्माद बढ़ाने में संलग्न है, तब भी हमारा राष्ट्र एक होकर अटल खड़ा है और राष्ट्रीय मजबूती की प्रक्रिया और भी सुदृढ़ होती जा रही है।

आंतरिक सुरक्षा की समस्या का मुकाबला करने से यह गति थमती नहीं है। स्थिति चुनौतीपूर्ण नजर आ सकती है और यह चुनौतीपूर्ण है परंतु इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि वह नियंत्रण से परे है। ऐसी चिंताएं विद्यमान हो सकती हैं कि बहुत से खतरों को विफल करने के लिए हमारा रक्षा तंत्र अपर्याप्त है। यह आलोचना हो सकती है कि आंतरिक सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए हमारे औजार पर्याप्त रूप से परिष्कृत नहीं हैं। स्पष्ट रूप से, हमें तकनीकी सिग्नलिंग और मानवीय गुप्तचर सेवा के अपने तंत्र की प्रभावशीलता की समीक्षा करने की ज़रूरत है। हमारे सुरक्षा बलों को उपलब्ध प्रशिक्षण और उपकरणों की भी सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की ज़रूरत है। मैं स्वीकार करूंगा कि और बहुत कुछ किया जा सकता है, और करने की ज़रूरत है, किया भी जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को यह राष्ट्रीय कार्य पूरी तेजी से, दक्षता और पूरी प्रतिबद्धता से करना चाहिए।

हमारी विदेश नीतियां सहायक पड़ोस रखने की इच्छा से निर्देशित की गई हैं। दुर्भाग्य से, हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों ने अतीत में आतंकवादियों और उन ताकतों को प्रोत्साहित किया है तथा उन्हें अपने यहां शरण दी है जो भारत विरोधी हैं। हमने कुछ निश्चित प्रतिरक्षाओं के जरिए ऐसी शत्रुता के असर को न्यूनतम करने की कोशिश की है। हमने जम्मू-कश्मीर में लाइन ऑफ कन्ट्रोल के साथ अपनी सीमाओं पर कंटीले तार लगाए हैं, जहां से बड़े पैमाने पर भारत में घुसपैठ होती थी। हम फिलहाल अपनी बांग्लादेश सीमा पर भी कंटीले तार लगा रहे हैं जहां से घुसपैठ की खबर मिली है।

इसके फलस्वरूप, पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे के कर्णधारों ने भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए अन्य चालाकियां शुरू कर दी हैं। नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ हो रही है और जम्मू-कश्मीर में लाइन ऑफ कन्ट्रोल के रास्ते यह पूरी तरह थमी नहीं है। हम जानते हैं कि समुद्री रास्ता अन्य विकल्प है जो अब इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ अवरोधक लगाए गए हैं, लेकिन हम 10 पाकिस्तानी आतंवादियों को रोकने में नाकाम रहे जो 26 नवंबर को कराची से समुद्र के रास्ते आए।

पिछले साल नवंबर में मुंबई में आतंकी हमला स्पष्ट रूप से पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा ने किया था। इस हमले में कुछ विदेशी भी मारे गए, उन विदेशी एजेंसियों सहित की गई जांच के आधार पर यह दर्शाने के पर्याप्त सबूत हैं कि इनमें जिस परिष्कृत और सैन्य विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया गया है उसे पाकिस्तान की कुछ आधिकारिक एजेंसियों का समर्थन ज़रूर था।

हम आतंकवाद के विविध सकेंद्रित तत्वों के अस्तित्व के बारे में जानते हैं जो हमारी सुरक्षा पर असर डालते हैं। मुंबई आतंकी हमला उस श्रेणी में आता है जिसे खासतौर पर विदेशी आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया है। आतंकवाद के कुछ ऐसे सकेंद्रित तत्व भी हैं जो प्रायः बाहरी ताकतों के सहयोग से आतंक को अंजाम देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अनिवार्य रूप से स्वदेशी प्रकृति के होते हैं।

आतंकवादी घटनाओं के हाल के पैटर्न से यह संकेत भी मिलता है कि ऐसे हमले भी बढ़ रहे हैं जिनके पेन-इंडियन और ट्रांस-नेशनल पहलू होते हैं। आतंकवादी नई तकनीक और नई दक्षताएं हासिल करने में समर्थ हैं। व्यापक जनसंहार करने वाले हमलों पर जोर बढ़ता जा रहा है। आतंकवादी संचार अत्याधुनिक हो चुका है। इंटरनेट और वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल कनेक्टिविटी का इस्तेमाल आतंकवादियों को बहुत छद्म रूप प्रदान करता है और विशेषज्ञों को उनका पता लगाने में कठिनाई होती है।

आजकल के हमले पहले की तुलना में कम बेतरतीब होते हैं। मुंबई के मामले में, हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा हितों के बीच निश्चित संबंध को समझा जा सकता है। विदेशियों, खासतौर पर पश्चिमी लोगों को लक्ष्य करना, स्वाभाविक रूप से यह संदेश देने का इरादा था कि पश्चिम और पश्चिमी निवेश के गंतव्य के रूप में भारत असुरक्षित है। हमें इस प्रकार के ठप्पे का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने की ज़रूरत है। हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़मीन पर अन्य प्रमुख आतंकी हमला न होने पाए। हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ आतंकवाद को हरगिज सहन न करने की नीति कार्यान्वित करनी चाहिए।

कुछ देशों ने हमारे देश की तरह आतंकवादियों के हाथों बार-बार और बहुत अधिक हिंसा झेली है और उसका सामना किया है। पिछले वर्ष के दौरान, दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, असम, मुंबई और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में आतंकवादी हमले किए गए हैं और प्रत्येक हमले के साथ परिष्करण स्तर और उन्नत होता गया है।

जो बात इस समय आतंकवाद को खासतौर पर और भी खतरनाक बनाती है वह संवेदनशीलता के ठप्पे के साथ आतंकवादी उपकरणों की तकनीकों और विधियों का बहुत अधिक परिष्कृत होना है। हमारे समक्ष यह प्रदर्शित करने की चुनौती है कि हमारे पास आतंकवादी तरीकों में बदलाव का मुकाबला करने के लिए क्षमता के साथ साथ परिष्कृत उपकरण हैं। इसलिए हम संकीर्ण सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें घटनाओं पर तुरंत सिर्फ संकीर्ण प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करनी चाहिए।

इस सम्मेलन में आपको आमंत्रित करने के लिए लिखे गए गृह मंत्रालय के पत्र में यही संदेश रेखांकित होता है। इस मोड़ पर अपनी संयुक्त इच्छा प्रदर्शित करना और यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि हम भविष्य में आतंकी हमलों से निपटने के लिए आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को प्रभावशाली ढंग से चाकचौबंद कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी दुनिया भर में गैर-सरकारी तत्वों को ताकतवर बना रही है और हम सबके लिए व्यापक रणनीति बनाना बहुत आवश्यक है जिसमें हर प्रकार के आतंकवाद को पराजित करने के लिए देश की बेहतरीन प्रौद्योगिकी और मानवीय क्षमताओं का संयोग हो।

गृहमंत्री उन अनेक उपायों पर पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं जो भावी आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु अतिरिक्त तंत्र खड़ा करने के लिए हाल ही के हफ्तों में उठाए गए हैं। मुख्य संदेश यह है कि हमें विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान में आने वाली बाधाओं को दूर करने की ज़रूरत है।

मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि हमें बेहतरीन गुप्तचर सूचना की ज़रूरत है तथा, और भी महत्तवपूर्ण रूप से, उपलब्ध गुप्तचर सूचनाओं का परिष्कृत आकलन और विश्लेषण करने की ज़रूरत है। अक्सर ये शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि एजेंसियां ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं जो कार्रवाई करने योग्य नहीं होती। हर गुप्तचर सूचना कार्रवाई योग्य होती है, तथापि यह हो सकता है कि वह विशिष्ट नहीं हो। यह उनकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है जो उस सूचना को आगे विकसित करने के लिए और टुकड़ों-टुकड़ों में बंटी सूचना को एकत्र करके समग्र रूप देने के लिए इसका आकलन करते हैं तथा जिनको प्रत्येक लीड पर हर संभव काम करना होता है।

सही समय पर जल्दी सूचना प्राप्त करना आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण है और हमें सभी अप्रिय आयोजन एवं घटनाओं को दर्ज करने के लिए गांव, खंड और जिला स्तर पर विस्तृत सूचना प्रणाली की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आज मोबाइल टेलीफोन आसान संचार का अवसर उपलब्ध कराता है। यहां तक कि समुद्र में मछली पकड़ने गए हमारे मछुवारे भी हमारे जल क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना की सूचना देने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि आतंकवाद रोधी किसी भी कार्रवाई के सफल होने की तब तक कोई उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक कि वह समुदाय के सहयोग पर आधारित न हो और इसलिए हमारे देश में विस्तृत सामुदायिक नीति तंत्र का बहुत महत्व है। मैं मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे इस आवश्यक कार्य को निजी तौर पर करें।

विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचना को उसके बाद साझा बिन्दु-जैसे मिलान और विश्लेषण के लिए हाल ही में बनाये गये मल्टी एजेंसी सेंटर, तक पहुंचाने के लिए समुचित रूप से दिशा देने की ज़रूरत है। इसलिए, उपलब्ध सूचना का मिलान करने के लिए देश भर में राज्य और निचले स्तर पर स्थानीय रूप से ये केंद्र बनाने की आवश्यकता होगी जहां संभावित आतंकवादी हालात पैदा होने की आशंका हो। अमरीका जैसे अन्य देशों जहां हमारी जैसी संघीय संरचना है, में आतंकवाद से स्थानीय स्तर पर समन्वय करने के लिए देश भर में ऐसे केंद्र फैले हैं।

व्यापक सूचना को कार्रवाई योग्य गुप्तचर जानकारी में बदलने के लिए संरचनात्मक विश्लेषणात्मक विधियों जैसी तकनीकों के इस्तेमाल के बिना विशाल आनुभविक डाटा बेस के उपयोगी परिणाम नहीं होंगे। खतरों के आकलन के मॉडल बनाने और कृत्रिम तंत्रिक नेटवर्क जैसे अनुप्रयोगों में मौजूदा विश्लेषणात्मक तकनीकों को जोड़ना होगा। महत्वपूर्ण ढांचागत संरचना का त्रिआयामी मॉडलिंग एक नया पहलू है जिसे शुरू करने की ज़रूरत है। विभिन्न हालात में, हमें वास्तविक संक्रिया सेंटर के बारे में भी सोचना होगा।

हाल ही में, मुझे संसद में यह कहने का मौका मिला कि हमारे लिए अपने देश में कहीं भी होने वाले प्रमुख आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए स्थायी संकट प्रबंधन समूह स्थापित करने का समय आ गया है। इसे अब स्थापित कर दिया गया है। हमने समुद्र के रास्ते असंयमित खतरों के विरूद्ध मैरीटाइम सुरक्षा मजबूत करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। हमने अपने वायु क्षेत्र के संबंध में मौजूद खामियों को दूर

करने के समन्वित उपाय किए हैं। हमारी आतंकवाद विरोधी ताकतों को बढ़ाने और मजबूत करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

हमें करीबी जांच और ध्यान देने के साथ साथ नए और उभरते हुए खतरों से निपटने के लिए अधिक तीव्र अनुक्रिया हासिल करने की उम्मीद है। हमारा लक्ष्य सम्पूर्ण सुरक्षा की परिकल्पना हासिल करना है।

इसके अतिरिक्त, मैं यहां वामपंथी उग्रवाद के खतरे का भी उल्लेख करना चाहूंगा। नक्सली समूह भी एक चुनौती हैं यद्यपि उसकी प्रकृति कुछ भिन्न है। वामपंथी उग्रवाद अब चार दशक पुराना हो चुका है, परंतु खतरा यह है कि समय के साथ इस आंदोलन की प्रकृति में बहुत बदलाव आ गया है। एक विचारधारा निर्देशित आंदोलन से अब यह ऐसे आंदोलन में बदल गया है जिसमें सैन्य प्रकृति हावी हो गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी संभवतः देश में एकमात्र ऐसा सैन्य संगठन है जिसकी अपनी गुरिल्ला सेना है, यद्यपि, अब भी, यह आनुपातिक रूप से मर्यादित है। आज संभवतः यह एकमात्र ऐसा उग्रवादी निकाय है जिसकी कठोर संगठनात्मक संरचना है। उनके पास हथियार बनाने के लिए कुछ अल्पविकसित क्षमताएं भी हैं। वे जिस तरह से हमले करते हैं वह तरीका परिष्कृत होता जा रहा है। आंदोलन में नई भर्ती की भी उनमें कोई कमी नजर नहीं आती।

देश में बहुत कम राज्य यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। यह आंदोलन अब फैल रहा है और अधिक जोशीला तथा सक्रिय हो रहा है, इसलिए हमें इस बात पर गंभीरता से मनन करना चाहिए कि इससे किस तरह प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि इस आंदोलन में अब भी कुछ वैचारिक अपील बाकी है। यह अब भी कुछ युवकों के आकर्षित करता है। इसलिए सही विधियों का चयन और समुचित रणनीति अपनाना महत्वपूर्ण है ताकि हम जो कार्रवाई करें वह आन्दोलन की वृध्दि को अधिक प्रोत्साहन न देती हो।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आतंकवाद पर सिर्फ सैन्य रूप में ही विचार नहीं करना चाहिए। आतंकी हमलों को रोकने के लिए सभी ज़रूरी उपाय करते समय, हमें साथ साथ बेहतर जांच और उत्कृष्ट गुप्तचर सेवा के जरिए यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवाद का विचार अवैध है। हमें वैश्विक समुदाय को यह समझाना चाहिए कि जो देश विदेश नीति के औजार के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करे, उसे अलग-थलग किया जाना चाहिए और ऐसे कृत्य का त्याग करने के लिए उसे बाध्य किया जाना चाहिए। हमें इस बिंदु पर दबाव बनाने के लिए जोरदार ढंग से बहस में संलग्न रहना चाहिए कि आतंकवाद के लिए नरम रूख का लम्बे समय तक समर्थन नहीं किया जा सकता। हमें यह दर्शाना चाहिए कि हम जैसा चौकस, बहुलवादी और धर्मनिरपेक्ष समाज आतंकवादी हमलों के विरूद्ध बेहतरीन रक्षा कवच है। माननीय मुख्यमंत्रियों, आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौती हैं। हमें इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी बुध्दि, ज्ञान और अनुभव को एकजुट करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे राष्ट्र के पास इस जंग में विजयी बनकर उभरने के लिए नई ताकत और इच्छाशक्ति की कमी नहीं है। मैं आपके विचार-विमर्श की सफलता की कामना करता हूं।

***